गरीबी के मुद्दे

Q1. उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, भारत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एक बड़ी आबादी से जूझ रहा है। भारत में गरीबी के बहुआयामी पहलुओं पर चर्चा करें और इसके उन्मूलन के लिए एक व्यापक रणनीति का सुझाव दें।

उत्तर: **भारत में बहुआयामी गरीबी और उन्मूलन के लिए एक रणनीति**

भारत की आर्थिक विकास की कहानी निर्विवाद रूप से प्रभावशाली है। फिर भी, आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे संघर्ष कर रहा है। यह विरोधाभास गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को उजागर करता है और इसके उन्मूलन के लिए एक व्यापक रणनीति की मांग करता है।

बहुआयामी गरीबी को समझना:

- गरीबी सिर्फ आय से परे है। इसमें बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी शामिल है:
- **गुणवत्ता की शिक्षा:** सीमित शैक्षिक अवसर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और कमाई की क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** खराब स्वास्थ्य देखभाल पहुंच उच्च रुग्णता और मृत्यु दर में बदल जाती है, जिससे उत्पादकता और कल्याण प्रभावित होता है।
- **स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल:** ये कमियाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देती हैं, संसाधनों पर और अधिक दबाव डालती हैं।
- **आश्रय:** अपर्याप्त आवास मौसम और बीमारी के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है।

इसके अलावा, जाति व्यवस्था और लिंग भेदभाव जैसे सामाजिक कारक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में बाधाएं पैदा करते हैं, जिससे पीढ़ियों तक गरीबी बनी रहती है।

गरीबी के कारण:

सामाजिक कारकों के अलावा, कई आर्थिक कारक भी गरीबी में योगदान करते हैं:

- **निम्न कृषि उत्पादकता:** खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच कृषि उत्पादन और आय में बाधा डालती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **अल्परोज़गारी और बेरोज़गारी:** तीव्र जनसंख्या वृद्धि रोजगार सृजन पर दबाव डालती है, जिससे कृषि में अल्परोजगार और उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।
- **संसाधनों का असमान वितरण:** भूमि और धन असमान रूप से वितरित हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा एक छोटे से वर्ग के बीच केंद्रित है, जो सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालता है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** परिवहन, संचार और भंडारण में खराब बुनियादी ढांचा उत्पादन और वितरण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे ग्रामीण आजीविका प्रभावित होती है।

इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि और जलवायु भेद्यता गरीबी को और बढ़ा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं।

उन्मूलन के लिए एक व्यापक रणनीति:

गरीबी उन्मूलन के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक और सामाजिक दोनों कारकों को संबोधित करे:

- **आर्थिक उपाय:**
  - **कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना:** प्रौद्योगिकी, सिंचाई और भूमि सुधार में निवेश से कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि हो सकती है।
  - **कौशल विकास:** उद्योग-प्रासंगिक कौशल और उद्यमशीलता (जैसे पीएमजीवाई और स्टैंड-अप इंडिया) पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
  - **बुनियादी ढांचे का विकास:** बेहतर सड़कें, भंडारण सुविधाएं और संचार नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों और अवसरों से जोड़ देंगे।

- **सामाजिक उपाय:**
  - **शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच:** शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जैसी योजनाएं व्यक्तियों को सशक्त बना सकती हैं और गरीबी चक्र को तोड़ सकती हैं।
  - **स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी पहल किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित कर सकती है।
  - **सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना:** सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण पहल संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:**
  - पीएमजीकेएवाई और एनएसएपी जैसी मौजूदा योजनाओं को सबसे कमजोर लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उचित लक्ष्यीकरण और कुशल कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
  - शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग पर सशर्त नकद हस्तांतरण की खोज सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **सतत विकास पर ध्यान दें:**
  - जलवायु-लचीली कृषि और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नीतियां आजीविका को पर्यावरणीय झटकों से बचा सकती हैं।

आगे का रास्ता:

गरीबी उन्मूलन के लिए सुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार सेवाएं प्रदान करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन और सतत विकास को संयोजित करने वाली व्यापक रणनीति के साथ गरीबी के बहुआयामी पहलुओं से निपटकर, भारत ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहां विकास वास्तव में समावेशी हो और किसी को भी पीछे न छोड़े।

Q2. तेजी से शहरीकरण भारत में गरीबी में कैसे योगदान दे सकता है और इसे कम कर सकता है?

तीव्र शहरीकरण: भारत में गरीबी के लिए एक दोधारी तलवार

भारत में तेजी से हो रहा शहरीकरण एक जटिल तस्वीर पेश करता है, जिसमें गरीबी में योगदान और उसे कम करने दोनों की क्षमता है। आइए सिक्के के दोनों पहलू देखें:

तीव्र शहरीकरण गरीबी में योगदान दे सकता है:

- **अनौपचारिक क्षेत्र:** प्रवासियों की आमद अक्सर औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन से आगे निकल जाती है, जिससे कई लोग कम वेतन वाले, अक्सर शोषणकारी, अनौपचारिक काम में धकेल दिए जाते हैं।

- **मलिन बस्तियाँ और अपर्याप्त आवास:** शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि से खराब स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के साथ भीड़भाड़ वाली झुग्गियां बन सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है और गरीबों के लिए संसाधनों पर और दबाव पड़ सकता है।
- **सामाजिक वियोग:** प्रवासन सामाजिक नेटवर्क को बाधित कर सकता है, जिससे व्यक्ति अलग-थलग और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं और बच्चे।
- **जीवनयापन की बढ़ती लागत:** शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर आवास, भोजन और परिवहन की लागत अधिक होती है, जो गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

तीव्र शहरीकरण गरीबी को कम कर सकता है:

- **रोजगार के अवसर:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर निर्माण, सेवाओं और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं।
- **ज्यादा पगार:** शहरी नौकरियाँ अक्सर ग्रामीण नौकरियों की तुलना में अधिक वेतन देती हैं, जिससे प्रवासियों को अपनी आजीविका में सुधार करने का मौका मिलता है।
- **सेवाओं तक बेहतर पहुंच:** शहरों में आम तौर पर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल तक बेहतर पहुंच होती है, जिससे शहरी गरीबों को फायदा हो सकता है।
- **प्रेषण:** प्रवासी अपने ग्रामीण परिवारों को पैसे वापस भेज सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण विकास में योगदान मिलेगा।

नकारात्मक प्रभावों को कम करने की रणनीतियाँ:

- **शहरी नियोजन:** उचित बुनियादी ढांचे के विकास, किफायती आवास और कुशल सार्वजनिक परिवहन में निवेश से शहरी गरीबों के लिए रहने की स्थिति में सुधार हो सकता है।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** प्रवासियों को प्रासंगिक कौशल से लैस करने से उनकी रोजगार क्षमता और बेहतर नौकरियों तक पहुंच बढ़ सकती है।
- **सामाजिक सुरक्षा जाल:** पेंशन और बेरोजगारी लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार शहरी गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है।
- **समावेशी विकास पर ध्यान दें:** अनौपचारिक क्षेत्र में सभ्य कार्य स्थितियों, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने वाली नीतियां कमजोर श्रमिकों की रक्षा कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

जबकि तेजी से शहरीकरण मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है, इसमें लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता भी है। शहरी नियोजन, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करके, भारत गरीबी में कमी के लिए शहरीकरण के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग कर सकता है और अपने नागरिकों के लिए अधिक न्यायसंगत भविष्य बना सकता है।

ISSUES OF POVERTY

Q1. Despite significant economic growth, India continues to grapple with a substantial population living below the poverty line. Discuss the multi-dimensional aspects of poverty in India and suggest a comprehensive strategy for its eradication.

Answer: Multi-Dimensional Poverty and a Strategy for Eradication in India

India's economic growth story is undeniably impressive. Yet, a significant portion of the population continues to struggle below the poverty line. This paradox highlights the multi-dimensional nature of poverty, demanding a comprehensive strategy for its eradication.

Understanding Multi-Dimensional Poverty:

Poverty goes beyond just income. It encompasses a lack of access to basic necessities like:

- **Quality education:** Limited educational opportunities restrict upward mobility and earning potential.
- **Healthcare:** Poor healthcare access translates to higher morbidity and mortality, impacting productivity and well-being.
- **Sanitation and safe drinking water:** These deficiencies lead to health issues, further straining resources.
- **Shelter:** Inadequate housing creates vulnerability to weather and disease.

Furthermore, social factors like the caste system and gender discrimination create barriers to accessing resources and opportunities, perpetuating poverty across generations.

Causes of Poverty:

Beyond social factors, several economic factors contribute to poverty:

- **Low agricultural productivity:** Fragmented landholdings, inadequate irrigation, and limited access to technology hinder agricultural output and income, especially in rural areas.
- **Underemployment and unemployment:** Rapid population growth puts pressure on job creation, leading to underemployment in agriculture and a lack of skilled workers for industries.
- **Unequal distribution of resources:** Land and wealth are unevenly distributed, with a large portion concentrated among a small segment, hindering social mobility.
- **Infrastructure bottlenecks:** Poor infrastructure in transportation, communication, and storage creates hurdles in production and distribution, impacting rural livelihoods.

Additionally, price rise and climate vulnerability can further exacerbate poverty, especially for those already struggling.

A Comprehensive Strategy for Eradication:

Eradicating poverty requires a multi-pronged approach that addresses both economic and social factors:

- **Economic measures:**
  - **Boosting agricultural productivity:** Investments in technology, irrigation, and land reforms can increase farm output and incomes.
  - **Skill development:** Programs focusing on industry-relevant skills and entrepreneurship (like PMGY and Stand-up India) can enhance employability.

- **Infrastructure development:** Improved roads, storage facilities, and communication networks will connect rural areas to markets and opportunities.

- **Social measures:**
  - **Universal access to education:** Schemes like Right to Education (RTE) can empower individuals and break the poverty cycle.
  - **Strengthening healthcare:** Initiatives like the National Health Mission can ensure access to affordable healthcare.
  - **Addressing social inequalities:** Affirmative action programs and women empowerment initiatives can promote equal access to resources and opportunities.
- **Direct benefit transfers:**
  - Existing schemes like PMGKAY and NSAP need proper targeting and efficient implementation to ensure benefits reach the most vulnerable.
  - Exploring cash transfers conditional on education or healthcare utilization can incentivize positive behaviour change.
- **Focus on sustainable development:**
  - Policies promoting climate-resilient agriculture and disaster management can protect livelihoods from environmental shocks.

The Way Forward:

Eradicating poverty requires good governance, transparency, and public participation. Technology and innovation can play a crucial role in delivering services, promoting financial inclusion, and facilitating market access.

By tackling the multi-dimensional aspects of poverty with a comprehensive strategy that combines economic empowerment, social inclusion, and sustainable development, India can move towards a future where growth is truly inclusive and leaves no one behind.

Q2. How can rapid urbanization contribute to, and mitigate, poverty in India?

Rapid Urbanization: A Double-Edged Sword for Poverty in India

Rapid urbanization in India presents a complex picture, with the potential to both contribute to and mitigate poverty. Let's explore both sides of the coin:

Rapid Urbanization Can Contribute to Poverty:

- **Informal sector:** The influx of migrants often outpaces job creation in formal sectors, pushing many into low-paying, often exploitative, informal work.
- **Slums and inadequate housing:** The rapid rise in urban population can lead to crowded slums with poor sanitation and infrastructure, creating health risks and further straining resources for the poor.
- **Social disconnection:** Migration can disrupt social networks, leaving individuals feeling isolated and vulnerable, especially women and children.
- **Rising cost of living:** Urban areas generally have higher costs for housing, food, and transportation, which can disproportionately impact the poor.

Rapid Urbanization Can Mitigate Poverty:

- **Job opportunities:** Cities offer a wider range of job opportunities in various sectors like construction, services, and manufacturing, compared to rural areas.
- **Higher wages:** Urban jobs often offer higher wages than rural ones, providing migrants with a chance to improve their livelihoods.
- **Improved access to services:** Cities generally have better access to healthcare, education, and social safety nets, which can benefit the urban poor.
- **Remittances:** Migrants can send money back to their rural families, boosting their income and contributing to rural development.

Strategies to Mitigate Negative Impacts:

- **Urban planning:** Investing in proper infrastructure development, affordable housing, and efficient public transportation can improve living conditions for the urban poor.
- **Skill development programs:** Equipping migrants with relevant skills can increase their employability and access to better jobs.
- **Social safety nets:** Expanding social security programs like pensions and unemployment benefits can provide a safety net for the urban poor.
- **Focus on inclusive growth:** Policies promoting decent work conditions, minimum wages, and access to social security in the informal sector can protect vulnerable workers.

Conclusion:-

While rapid urbanization can exacerbate existing inequalities, it also holds the potential to lift people out of poverty. By implementing effective policies for urban planning, skill development, and social inclusion, India can harness the positive aspects of urbanization for poverty reduction and create a more equitable future for its citizens.

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR